(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (e) Central Assistance by the Planning Commission for the State Plans including that of Gujarat is privided in the form of block loans and block grants. The utilisation of this assistance for the balanced development of the different regions of the State is primarily the responsibility of the State Government.

राज्यों द्वारा विकास केन्द्रों के संबंध में भेजी गई परियोजना -रिपोर्ट

3072. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों ने विकास केन्द्रों के संबंध में अपनी परियोजना रिपोर्ट भेजी दी है ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकास केन्द्रों के संबंध में केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धन राशि प्रदान की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजगा आयोग को किसी राज्य द्वारा विकास केन्द्रों के संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Financial assistance to Punjab

3073. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have recently allocated the financial assistance to Punjab for the development of agricultural and industrial sectors of the State, and

(b) if so, the details thereof during 1990-91 and 1991-92?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) Central assistance by the Planning Commission for the State Plans including that of Punjab, is provided in the form of block loans and block grants. The outlay for the Annual Plans 1990-91 and 1991-92 for Agriculture and Allied Activities and Industry and Minerals is as follows:—

(Rs. in crores)

Item	Outlay for 1990-91	Outlay for 1991-92
1. Agriculture and Allied Activities	90.50@	88.35*
2. Industry and Minerals	47.00@	64.00

* Excludes Rs. 8.80 crore for the Scheme of equity base to the cooperatives which was dropped later on by the Planning Commission.

@ Tentative.

Implementation of Centrally sponsored schemes in Northern States

3074. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has conducted any study regarding effective implementation of various centrally sponsored schemes in Northern States;

(b) if so, the details thereof; State-wise;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether any steps have been taken/proposed to be taken to make these schemes more effective?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (d) The Planning Commission has not conducted any separate study regarding effective implementation of various Centrally sponsored schemes in Northern States of Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. Scheme are monitored by the administrative ministries concerned. However, the Planning Commission generally reviews the implementation of Plan schemes during the Annual Plan discussions with the States.

गुजरात में गांवों को सड़कों से जोड़ना

3075. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1000 से 1500 तक की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में इस योजना के अन्तर्गत अब तक जिलेवार कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों में सड़कों से जोड़े गये गांवों की जिला-वार संख्या के बारे में सूचना नहीं रखता है।

(ग) चूंकि ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

गुजरात में डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० योजनाएं

3076. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने जिलों में डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० योजनायें आरम्भ की गई हैं ;

(ख) गत वर्ष के दौरान इन जिलों में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात के कौन-कौन से जिलों में ये योजनायें आरम्भ किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) गुजरात में ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) 13 जिलों में शुरू की गई है।

(ख) प्रमुख कार्य हैं—सिलाई, निटिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिले-सिलाये कपड़े, कालीन की बुनाई, डेरी, बकरी पालन, मत्स्यपालन तथा मुर्गीपालन आदि।

(ग) अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

Target fixed under NREP for Gujarat

3077. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what were the targets fixed for Gujarat during 1991-92 under the National Rural Employment Programme and how far the targets have been achieved so far;